

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1852

उत्तर देने की तारीख : 31.07.2025

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु ऋण सुविधाएं

1852. प्रो. सौगत राय:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को बाधित करने वाली सबसे बड़ी चुनौतियां अपर्यास पूंजी और ऋण सुविधाओं से संबंधित हैं;
- (ख) यदि हां, तो एमएसएमई के लिए पूंजी और ऋण सुविधाओं का पर्यास प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का व्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त क्षेत्र में खराब और अपर्यास अवसंरचनात्मक सुविधाओं की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या सरकार ने अपर्यास पहुंच और विपणन संपर्कों संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ङ) देश में पंजीकृत/कार्यरत एमएसएमई की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(मुश्त्री शोभा करांदलाजे)

(क) एवं (ख) : देश में एमएसएमई के लिए पर्यास पूंजी प्रवाह तथा क्रेडिट सहायता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- i. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) जैसी स्कीमें जिसमें विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 90% तक गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 10 करोड़ रुपए (दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी) की सीमा तक कोलेटरल मुक्त ऋण का प्रावधान है।
- ii. प्रधान मंत्री रोजगार सूजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए क्रमशः 50 लाख रुपए तथा 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ 35% तक की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।
- iii. विशेष क्रेडिट लिंकड केपिटल सब्सिडी स्कीम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली एमएसई के लिए संयंत्र तथा मशीनरी/उपकरणों की खरीद के लिए संस्थागत वित पर 25% सब्सिडी का प्रावधान है।
- iv. पीएम विश्वकर्मा स्कीम (पीएमवी) की शुरुआत दिनांक 17.09.2023 को 18 पारंपरिक व्यवसायों में अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले देश भर के कारीगरों तथा हस्तशिल्पियों को सम्पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।
- v. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड की स्थापना उन एमएसएमई में इक्विटी निधियन के रूप में 50,000 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए की गई जिनमें विकसित तथा बड़ी इकाई बनने की क्षमता और संभावना हो। इस फंड के तहत, भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वैंचर केपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

(ग) : देश भर में ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं और मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) स्थापित करने तथा नए/मौजूदा औद्योगिक संपदाओं/फ्लेटेड फैक्ट्री परिसरों में ढांचागत सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए भारत सरकार के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) : सरकार ने देश भर में विपणन लिंकेज की स्थापना करने के लिए अनेक पहलें की हैं। खरीद और विपणन सहायता (पीएमएसएस) स्कीम, एमएसई को व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, वैंडर विकास कार्यक्रमों, आधुनिक पेकेजिंग तकनीक, ई-कॉर्मर्स प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से बाजार तक पहुँच बढ़ाने के लिए लाभ प्रदान करती है।

मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के तहत, केंद्रीय/राज्य सरकार के पात्र संगठनों और उद्योग संगठनों को विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/केता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए निश्चित बाजार शेयर का प्रावधान है। यह नीति (वर्ष 2018 में संशोधित) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% की खरीद तथा महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से 3% की खरीद सहित एमएसई से वार्षिक खरीद का 25% खरीदना अधिदेशित करती है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के तहत एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल एक बिजनेस से बिजनेस (बी2बी) पोर्टल है, जिसमें भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऑनलाइन विपणन सुविधा प्रदान की जाती है।

(ङ) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, देश में पंजीकृत एमएसएमई की राज्य-वार संख्या अनुबंध-I पर हैं।

“एमएसएमई हेतु ऋण सुविधाएं” पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1852, जिसका उत्तर दिनांक 31.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (ड) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

उद्यम एवं योगी के तहत 01.07.2020 से 15.07.2025 तक राज्य/संघ शासित राज्य-वार पंजीकृत कुल उद्यम					
क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	संख्या	लघु	मध्यम	कुल
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	19,261	157	3	19,421
2	आंध्र प्रदेश	33,60,676	16,491	942	33,78,109
3	अरुणाचल प्रदेश	39,037	344	19	39,400
4	असम	11,83,889	6,523	519	11,90,931
5	बिहार	35,73,259	11,635	560	35,85,454
6	चंडीगढ़	68,200	1,247	124	69,571
7	छत्तीसगढ़	11,35,360	8,198	701	11,44,259
8	दिल्ली	11,91,761	27,734	2,689	12,22,184
9	गोवा	1,12,106	1,094	79	1,13,279
10	गुजरात	36,99,208	53,058	4,124	37,56,390
11	हरियाणा	16,69,870	22,580	1,729	16,94,179
12	हिमाचल प्रदेश	2,91,899	2,507	208	2,94,614
13	जम्मू और कश्मीर	7,36,820	3,162	203	7,40,185
14	झारखण्ड	13,17,404	5,758	349	13,23,511
15	कर्नाटक	43,32,188	30,775	2,238	43,65,201
16	केरल	15,76,019	12,627	744	15,89,390
17	लद्दाख	18,480	112	2	18,594
18	लक्ष्मीपुर	2,208	-	-	2,208
19	मध्य प्रदेश	41,33,259	19,307	1,150	41,53,716
20	महाराष्ट्र	85,51,716	72,793	6,694	86,31,203
21	मणिपुर	1,47,987	412	17	1,48,416
22	मेघालय	53,908	393	34	54,335
23	मिजोरम	44,951	207	6	45,164
24	नागालैंड	60,701	170	16	60,887
25	ओडिशा	20,44,179	9,787	581	20,54,547
26	पुडुचेरी	94,030	654	62	94,746
27	पंजाब	18,22,767	16,546	1,205	18,40,518
28	राजस्थान	37,35,958	26,543	1,598	37,64,099
29	सिक्किम	28,908	158	13	29,079
30	तमिलनाडु	52,70,701	38,540	2,735	53,11,976
31	तेलंगाना	25,47,334	19,604	1,749	25,68,687
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	29,903	901	132	30,936
33	त्रिपुरा	2,71,441	679	45	2,72,165
34	उत्तर प्रदेश	70,62,336	39,018	2,475	71,03,829
35	उत्तराखण्ड	5,39,209	3,945	270	5,43,424
36	पश्चिम बंगाल	45,53,732	23,323	1,706	45,78,761
	कुल:-	6,53,20,665	4,76,982	35,721	6,58,33,368

स्रोत: उद्यम पंजीकरण पोर्टल